भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1611
उत्तर देने की तारीख 13 मार्च 2025

आंध्र प्रदेश में दूरसंचार सुविधाएं

1611 श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डीः

क्या ***संचार*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में 1,500 से अधिक गांव दूरसंचार सुविधाओं से वंचित हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे सबसे अधिक गांव (1,000) विशाखापत्तनम जिले में हैं, जिनमें दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या मंत्रालय द्वारा इन सभी जिलों को दूरसंचार सुविधाओं से जोड़ने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) जनवरी 2025 तक, आंध्र प्रदेश के 17,328 गांवों में से (भारत के महारजिस्ट्रार के आंकड़ों के अनुसार) 16,349 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है। विशाखापत्तनम जिले में, 3,261 गांवों में से 2,655 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

सरकार आंध्र प्रदेश सहित देश के ग्रामीण, जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में 4जी मोबाइल टावरों की संस्थापना के माध्यम से दूरसंचार कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के तहत विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है। फरवरी 2025

तक, डीबीएन द्वारा वित्तपोषित मोबाइल स्कीमों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में 1,668 टावर चालू किए जा चुके हैं, जिससे 2,846 गांवों को 4जी मोबाइल कवरेज मिल रहा है।

भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन आदि जैसी ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रिंग टोपोलॉजी में देश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को अनुमोदित किया है जिसमें मौजूदा नेटवर्क को अपग्रेड करना और लगभग 3.8 लाख गैर-जीपी गांवों में मांग के आधार पर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना शामिल है।

******